NEED 24 NEWS
हर खबर, हर शहर

ताज़ा खबर | वर्ष-01 अंक-182 | संपादक: Mukesh Giri | 01 जुल. 2026

मेघों का घर मेघालय

शिक्षा

मेघालय स्वास्थ्य मंत्री: यूटीएम मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ का ऋण प्रस्ताव अस्वीकृत

मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री ने खुलासा किया है कि यूटीएम मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त ऋण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है।

मेघालय राज्य ने अपने चिकित्सा शिक्षा बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, 200 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त ऋण के लिए एक अनुरोध को ठुकरा दिया गया है। यह ऋण यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेघालय (यूटीएम) के लिए मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं की स्थापना और विस्तार हेतु था। प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सूचित किया गया था, हालांकि अस्वीकृति के विशिष्ट कारणों के संबंध में अधिक जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं कराई गई। यह विकास यूटीएम के लिए चिकित्सा शिक्षा संसाधनों के नियोजित विस्तार में एक विराम का संकेत देता है, जिसमें राज्य सरकार ने प्रस्तावित वित्तीय सहायता के विरुद्ध जाने का विकल्प चुना है।

स्रोत: India Today NE

चित्र: Wikimedia Commons / FrederickIisg

अपराध

मेघालय HC ने सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी, राज्य की SC जाने की मंशा

चित्र: Wikimedia Commons / Aiban-03

मेघालय उच्च न्यायालय ने सोनम रघुवंशी नामक व्यक्ति को पहले दी गई जमानत रद्द करने के राज्य सरकार के प्रयास के विरुद्ध फैसला सुनाया है। न्यायालय के इस निर्णय का अर्थ है कि जमानत आदेश बरकरार रहेगा और राज्य की अपील खारिज कर दी गई है। इस खारिज के बाद, राज्य सरकार के लिए जमानत को चुनौती देने के रास्ते काफी सीमित हो गए हैं। यदि प्रशासन इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके पास प्राथमिक उपाय के तौर पर भारत की सर्वोच्च अदालत, यानी सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करना ही बचा है। मामले के विशिष्ट विवरण या वे आधार जिन पर राज्य ने जमानत रद्द करने की मांग की थी, प्रारंभिक रिपोर्ट में विस्तृत नहीं किए गए हैं। मुख्य ध्यान उच्च न्यायालय स्तर पर न्यायिक परिणाम और सरकार के लिए संभावित अगले कदमों पर केंद्रित है।

स्रोत: India Today NE

बिज़नेस

मेघालय के सीएम ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मासिक पुरस्कार शुरू किया

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने 'अचीवर्स ऑफ द मंथ' नामक एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य पूरे राज्य में उद्यमी भावना को बढ़ावा देना और उसका जश्न मनाना है। कार्यक्रम का लक्ष्य उन व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए एक मंच प्रदान करना है जो अपने उद्यमों में असाधारण नवाचार और सफलता का प्रदर्शन करते हैं। मासिक आधार पर उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देकर, राज्य सरकार का इरादा अधिक नागरिकों को उद्यमी मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस कदम से एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहि...

स्रोत: Northeast Today

राजनीति

मेघालय ने असम सीमा विवाद समाधान के लिए पैनलों का पुनर्गठन किया

खबरें एआई द्वारा स्रोतों से संकलित। चित्र स्रोत सहित।

चित्र: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office

मेघालय सरकार ने अपने पड़ोसी राज्य असम के साथ सीमा संबंधी लंबित मुद्दों को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अंतर-राज्यीय सीमा पर विवाद के शेष बिंदुओं के समाधान में तेजी लाने और उन्हें संबोधित करने के लिए नई राज्य-स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। पैनलों के इस पुनर्गठन से अंतर-राज्यीय सीमा विवादों के अंतिम समाधान की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। पिछले समितियों को शेष मतभेदों को दूर करने के लिए आवश्यक बातचीत और चर्चा की गति को तेज करने के उद्देश्य से पुनर्गठित किया गया है। हालांकि नई समितियों की संरचना या शेष विवादों की सटीक प्रकृति के बारे में विशिष्ट विवरण नहीं दिए गए हैं, यह कार...

स्रोत: India Today NE

विज्ञापन

मौसम

घाना में बाढ़ से 24 से अधिक लोगों की मौत

घाना से दुखद खबर सामने आई है जहां व्यापक बाढ़ के कारण कम से कम 24 लोगों की जान चली गई है। गंभीर मौसम की स्थिति ने स्थानीय बुनियादी ढांचे को पस्त कर दिया है और इससे बड़े पैमाने पर जनहानि हुई है। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित विशिष्ट क्षेत्रों और मौतों के कारणों के बारे में अभी भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि, पुष्टि की गई मौतों की संख्या कम से कम 24 लोगों की है। यह प्राकृतिक आपदा चरम मौसम की घटनाओं के प्रति समुदायों...

स्रोत: The Meghalayan Express

अपराध

मेघालय सीएम: ICCC ने पुलिस को केस सुलझाने में की मदद, अब पूरे राज्य में विस्तार की योजना

मेघालय के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) ने राज्य पुलिस बल की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल के महीनों में, ICCC ने कथित तौर पर कई मामलों के सफल समाधान में मदद की है। इस सफलता के बाद, राज्य सरकार अब ICCC की पहुंच का विस्तार करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में प्रणाली को लागू करने की योजनाओं का संकेत दिया है, जिससे यह पता चलता है कि इसके लाभों को मेघालय में कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए अभिन्न माना जाता है। ICCC को पुलिस सहित विभिन्न सरकारी विभागों के भीतर दक्षता और समन्वय को बढ़ाने के उद्देश्य से एक तकनीकी पहल के रूप में समझा जाता है। मामलों को सुलझाने में इसका सफल अनुप्रयोग पूरे राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा और शासन को मजबूत करने की इसकी क्षमता की ओर इशारा करता है।

स्रोत: shillongtoday.com

चित्र: Wikimedia Commons / Ministry of Home Affairs

खबरें एआई द्वारा स्रोतों से संकलित। चित्र स्रोत सहित।